शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 50 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 8 – 15 दिसम्बर 2025 मूल्य पांच रूपये

मंडी में कांग्रेस का जन संकल्प सम्मेलन

तीन वर्षों की उपलब्धियों का लेखा–जोखा

शिमला/शैल। मण्डी के पड्डल मैदान में हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित जन संकल्प सम्मेलन राज्य की विकास यात्रा, नीतिगत बदलावों और जनकल्याणकारी उपलब्धियों का व्यापक मंच बना। प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति ने आयोजन को जनसमर्थन का प्रतीक बना दिया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के संबोधनों में सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य के संकल्पों को विस्तार से रखा गया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार के तीन वर्ष केवल एक कार्यकाल का आंकड़ा नहीं, बल्कि जनता के विश्वास, पारदर्शी सुशासन, आर्थिक सुधारों और जन–समर्पित नीतियों की यात्रा हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने सत्ता संभाली, उस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति गंभीर चुनौतियों से घिरी थी। इसके बावजूद सरकार ने कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय लेकर हिमाचल को आत्मनिर्भर, समृद्ध और हरित राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्रत्येक नीति और योजना का केंद्र बिंदु आम जनता रही है। चुनाव के दौरान दी गई 10 गारंटियों में से सात को तीन वर्षों में पूरा किया गया। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को पहली कैबिनेट बैठक में लागू कर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य और सम्मान को ध्यान में रखकर लिया गया।

महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकताओं में रखते

हुए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की गई, जिसके तहत पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रतिमाह 1500 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना ने महिलाओं को आर्थिक संबल दिया है और पारिवारिक निर्णयों में उनकी भूमिका को मजबूत किया है। इसके साथ ही विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है।

युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार सृजन को लेकर सरकार ने कई नई पहलें कीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकार अब तक 23 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान कर चुकी है। इसके अतिरिद्र ई–टैक्सी योजना, स्वरोजगार कार्यक्रम और विदेशों में रोजगार के अवसरों के लिए भी युवाओं को सहयोग दिया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत, 100 स्कूलों में सीबीएसई पाठयक्रम लागू करने और 20 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे–बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना जैसे फैसलों से शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में भी दिखाई दिया है।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया जा रहा है। चमियाना अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई है, जिससे जटिल उपचार अब प्रदेश में ही संभव हो सका है। आने वाले समय में चिकित्सा ढांचे को और मजबूत किया जायेगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किसानों और पशुपालकों के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए गए। गाय और भैंस के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया, जिससे हिमाचल दूध पर एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य बना। गोबर खरीद योजना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और बागवानी क्षेत्र में यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली लागू कर किसानों और बागवानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया गया।

प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में भारी बारिश से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र से विशेष सहायता न मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से राहत पैकेज जारी किए और मुआवजे की राशि में वृद्धि की। उन्होंने कहा कि आपदा के समय सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी।

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने जन संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष संघर्ष, संवेदनशीलता और सेवा की मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने आर्थिक संकट और प्राकृतिक आपदाओं जैसी गंभीर चुनौतियों के बावजूद विकास का मार्ग नहीं छोड़ा। रजनी पाटिल ने कहा कि यह सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का कार्य करती है।

उन्होंने महिला कल्याण योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के आत्मसम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है। रजनी पाटिल ने कहा कि युवाओं के लिए शुरू की गई स्टार्टअप और रोजगार योजनाएं भविष्य निर्माण का आधार हैं। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में किए गए सुधारों को भी दूरदर्शी बताते हुए कहा कि इनका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा।

रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने कांग्रेस सरकार पर जो विश्वास जताया है, सरकार उसे विकास और सुशासन के माध्यम से मजबूत कर रही है।

उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार के तीन वर्षों की उपलब्धियां केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर हुए वास्तविक कार्यों का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पेयजल, बुनियादी ढांचा, षि, बागवानी और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ठोस फैसलों से प्रदेश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सुशासन को मजबूत किया है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार, राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे और विशेष अदालतों के माध्यम से बड़ी संख्या में लंबित मामलों का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम नागरिक को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना है।

उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा देना सरकार की संवेदनशील सोच को दर्शाता है। यह योजना किसी चुनावी वादे का हिस्सा नहीं थी, बल्कि मानवीय मूल्यों से प्रेरित निर्णय था।

उप–मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और पशुपालकों के लिए लिए गए फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। रोजगार सृजन के क्षेत्र में सरकार

शेष पृष्ठ 8 पर.....

नौणी विश्वविद्यालय का 14वां दीक्षांत समारोह राज्यपाल ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया

शिमला/शैल। डॉ.वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी का 14वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल शिव

प्रताप शुक्ल ने की। समारोह में राज्यपाल ने 12 स्वर्ण पदक प्रदान किए, जिनमें 9 पदक छात्राओं को मिले। इसके अलावा 518 छात्रों को प्रमाण पत्र और 855 को डिग्रियां प्रदान की गई।

राज्यपाल ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह केवल शैक्षणिक उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज और किसानों के प्रति नई जिम्मेदारियों की शुरुआत है। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, ब्लूबेरी, मैकाडामिया नट और कॉफी जैसे उच्च मूल्य वाले फलों को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट शोध कार्यों, प्रकाशनों और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय एमओयू को सराहा। साथ ही नशामुक्ति अभियान में युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए राज्य को नशामुक्त बनाने का आहवान किया।

विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित कृषि वैज्ञानिक चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार ने कहा कि बागवानी, कृषि और वानिकी हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से राष्ट्रीय बागवानी मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन और BIOE-3 नीति में योगदान देने की अपील की।

कुलपति डॉ. राजेश्वर चंदेल ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि एनआईआरएफ-2025 में विश्वविद्यालय ने कृषि विश्वविद्यालयों में 20वां तथा आईआईआरएफ रैंकिंग में कृषि एवं बागवानी श्रेणी में 11वां स्थान प्राप्त किया है। विस्तार गतिविधियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों किसानों एवं हितधारकों को लाभ पहुंचाया गया है।

समारोह में विधायक विनोद सुल्तानपुरी, वरिष्ठ अधिकारी, विश्वविद्यालय सीनेट सदस्य, शिक्षण स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे।

विश्वसनीय और ज़िम्मेदार मीडिया लोकतंत्र की रीढ़: उप-मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विश्वसनीय और ज़िम्मेदार मीडिया लोकतंत्र की रीढ़ है। वह चंडीगढ़ में समाचार-पत्र एवं समाचार एजेंसी संगठन महासंघ की दो दिवसीय अखिल भारतीय मीट के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे, जिसका आयोजन द ट्रिब्यून कर्मचारी संघ ने किया।

उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया आज भी विश्वसनीयता का प्रमुख माध्यम है और समाज, प्रशासन तथा सरकार के लिए ठोस फीडबैक प्रदान करता है। मीडिया से प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रदेश सरकार जनकल्याणकारी नीतियों में सुधार और सकारात्मक बदलाव कर रही है। नकारात्मक समाचारों को भी रचनात्मक रूप से लेते हुए योजनाओं की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विकास, कल्याण और गरीबों के हित को प्राथमिकता दी जा रही है। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत लगभग छः हजार अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रूप में अपनाए जाने और शिमला में पेयजल समस्या के समाधान के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपये की योजना की जानकारी दी।

उन्होंने मीडिया से प्रदेश हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देने का आग्रह किया तथा चंडीगढ़ में हिमाचल के 7.19 प्रतिशत हिस्से और बीबीएमबी परियोजनाओं में राज्य के हिस्से का विषय भी उठाया।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री ने द ट्रिब्यून कर्मचारी संघ के मानवीय कार्यों के लिए एक लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की। कार्यक्रम में द ट्रिब्यून कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनिल गुप्ता, कॉन्फेडरेशन ऑफ न्यूजपेपर के अध्यक्ष रास बिहारी, महासचिव एम.एस. यादव सहित देशभर से आये मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

प्रदेश सरकार के चिट्टा-मुक्त अभियान को मिली नई गति

राज्यव्यापी विशेष कारवाई में 254 एकांत स्थलों की जांच, 596 वाहनों की तलाशी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों पर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पूरे राज्य में एक विशेष, सुनियोजित और सघन एंटी-चिट्टा अभियान चलाया। यह अभियान 15 नवम्बर से आरंभ राज्यव्यापी एंटी-चिट्टा जन-आन्दोलन के तहत 'चिट्टा-मुक्त हिमाचल' के लक्ष्य को मजबूती देने के उद्देश्य से संचालित किया गया।

अभियान के तहत पुलिस ने प्रदेशभर में चिन्हित निर्जन एवं अर्ध-सार्वजनिक स्थलों-सुनसान पहाड़ी ढलानें, जंगल क्षेत्र, खाली भवन, कमरे, पार्किंग स्थल, नदी-नालों के किनारे, पुराने बस स्टैंड और गैराज शेड का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 254 ऐसे स्थलों की आकस्मिक तलाशी ली गई, वहीं 596 वाहनों की भी जांच की गई।

यह विशेष कारवाई सभी पुलिस रेंजों में एक समान प्रभावी ढंग से लागू की गयी। दक्षिणी रेंज के सोलन, किन्नौर, सिरमौर तथा बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्रों में व्यापक तलाशी ली गयी। केंद्रीय रेंज के मंडी, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों में सघन निरीक्षण किया गया, जबकि उत्तरी रेंज के कांगड़ा, नूरपुर, देहरा, चंबा और ऊना जिलों में चिन्हित स्थलों पर विशेष कारवाई अमल में लायी गयी।

अभियान के दौरान 301 व्यक्तियों की जांच व काउंसलिंग की गई, जिनमें से नौ व्यक्तियों के रक्त व मूत्र के नमूने सुरक्षित किये गये। एनडीपीएस अधिनियम सहित अन्य विधिक प्रावधानों के तहत नौ आपराधिक मामले दर्ज किए गये। वहीं एकांत स्थलों पर पाये गये अन्य व्यक्तियों को आवश्यक परामर्श, दस्तावेजी प्रक्रिया और काउंसलिंग के बाद उनके परिजनों को सौंपा गया।

पुलिस विभाग के अनुसार यह राज्य-स्तरीय एंटी-चिट्टा अभियान पूरी तरह खुफिया सूचना आधारित और अंतर-जिला समन्वय के साथ संचालित किया गया, ताकि कारवाई विधिसम्मत, सुरक्षित और प्रभावी बनी रहे। अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को चिट्टे और अन्य नशों की गिरफ्त में आने से रोकना तथा एकांत स्थलों पर पनप रही समूह-आधारित नशा प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना है।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की कि चिट्टा अथवा किसी भी प्रकार के नशे से संबंधित सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 112 या नजदीकी पुलिस थाना में दें। सूचना देने वालों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

नौणी विवि एवं अनुसंधान केन्द्रों पर शीतोष्ण फलदार पौधों की वार्षिक बिक्री शुरू

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी तथा विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों और अनुसंधान स्टेशनों में बागवानों के लिये शीतोष्ण फलदार पौधों की वार्षिक बिक्री पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर शुरू

हो गयी है। फल रोपण सामग्री की इस वार्षिक बिक्री में हिमाचल प्रदेश सहित आसपास के राज्यों से किसान- बागवान बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों पर पहुंचे।

बिक्री के दौरान किसानों ने सेब, नाशपाती, खुमानी, आड़ू, चेरी, कीवीफ्रूट, अखरोट, अनार, प्लम और जापानी फल सहित विभिन्न फलों की किस्मों के पौधे खरीदे। पहले ही दिन नौणी स्थित विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की तीन नर्सरियों-फल विज्ञान विभाग की नर्सरी, मॉडल फार्म और बीज विज्ञान-के अलावा कंडाघाट, रोहड़ू के कृषि विज्ञान केंद्र तथा मशोबरा और शारबो (किन्नौर) स्थित अनुसंधान केंद्रों से 362 किसानों ने 15,250 पौधे खरीदे।

इसके अतिरिक्त, कुल्लू जिले के बजौरा में विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण स्टेशन में 8 दिसम्बर से पौधों की बिक्री शुरू हो चुकी है। यहां से अब तक 164 किसानों ने विभिन्न फलों की किस्मों के 4,596 पौधे खरीदे हैं। इस प्रकार अब तक कुल 526 किसानों को 19,846 पौधे बेचे जा चुके हैं। इस वर्ष किसानों में फलों की खेती के विविधीकरण को लेकर विशेष रुचि देखने को मिल रही है। बिक्री के दौरान सेब की विभिन्न किस्मों के साथ-साथ जापानी फल, कीवी और अन्य गुठलीदार फलों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय स्टेशनों पर इस वर्ष बिक्री के लिए 1.8 लाख से अधिक फलदार पौधे उपलब्ध हैं। यह बिक्री पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आगामी दिनों में भी जारी रहेगी।

खाद्यान्न सैंपल एकत्र करने के लक्ष्यों में वृद्धि पर जोर:डॉ. कत्याल

शिमला/शैल। राज्य खाद्य आयोग हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. एस.पी. कत्याल ने नागरिक आपूर्ति के माध्यम से वितरित किए जा रहे खाद्यान्न के सैंपल एकत्र करने के

लक्ष्यों में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। वे मंडी जिला में खाद्य सुरक्षा, पोषण कार्यक्रमों और उचित मूल्य दुकानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

डॉ. कत्याल ने मिड-डे मील की गुणवत्ता की नियमित जांच, विद्यालयों के मासिक निरीक्षण तथा भोजन तैयार करने वाले कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने महिला एवं वृद्ध आश्रमों में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन और पोषण की गुणवत्ता की निगरानी तथा आश्रितों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड नियमित रखने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने स्वास्थ्य एवं खाद्य विभागों को संयुक्त रूप से खाद्य सुरक्षाऔर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान सुदृढ़ करने को कहा। साथ ही, आपदा के दौरान निर्बाध खाद्य आपूर्ति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और भविष्य के लिए इन अनुभवों को दस्तावेजी रूप देने पर बल दिया। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार, जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति ब्रिजेन्द्र सिंह पठानिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

प्रदेश की 234 पंचायतों में नशा निवारण समितियों की समकालिक बैठकें

शिमला/शैल। नशा-मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश की 234 अत्यधिक नशा-प्रभावित पंचायतों में नशा निवारण समितियों की समकालिक बैठकें आयोजित की गई। यह पहल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार की गयी।

इन बैठकों का आयोजन 2 दिसम्बर को धर्मशाला में हुई 6वीं राज्य-स्तरीय बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना में किया गया। बैठकों का उद्देश्य पंचायत स्तर पर सामुदायिक सहभागिता को सशक्त बनाना, नशे की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना तथा पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित संबंधित विभागों के समन्वय से ठोस कार्ययोजना तैयार करना रहा।

बैठकों में नशा तस्करी से जुड़ी स्थानीय सूचनाओं की समीक्षा की गई और समुदाय-आधारित जागरूकता अभियानों के साथ आगामी रोकथाम व प्रवर्तन रणनीतियों पर चर्चा हुई। इन प्रयासों से नशा-निवारण अभियान को जन-आन्दोलन का स्वरूप देने पर बल दिया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की कि नशे या चिट्टा से संबंधित किसी भी सूचना को तुरंत 112 या नजदीकी पुलिस थाना में साझा करें। सूचनादाताओं की पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी।

जनजातीय सलाहकार परिषद् की 50वीं बैठक सम्पन्न, अनुसूचित क्षेत्रों में विकास को नई दिशा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में

अभूतपूर्व विकास हुआ है और ये क्षेत्र आज प्रदेश के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक समृद्ध और सम्पन्न हैं। वह यहां हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद् की 50वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बस व ट्रैवलर वाहनों की खरीद पर पात्र युवाओं को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी तथा सड़क कर में चार माह की छूट दी जाएगी। सौर ऊर्जा क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए 250 किलोवाट से एक मेगावाट तक की परियोजनाओं पर ब्याज उपदान भी प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने बर्फबारी वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा कि पांगी के धनवास और स्पीति के रोंगटोंग में सौर ऊर्जा संयंत्र शीघ्र कार्यशील किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने शिपकी-ला से कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा व्यापार शुरू करने के प्रयासों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय और सामाजिक सूचकांक प्रदेश में अग्रणी हैं। सरकार नौतोड़ स्वीकृति, आधारभूत ढांचे के विस्तार और स्वास्थ्य, शिक्षा व सड़क सुविधाओं को मजबूत करने को प्राथमिकता दे रही है।

बैठक में बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2025-26 के लिए 638.73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बैठक में मंत्रीगण, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और परिषद् के सदस्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल निकेतन के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली के द्वारका स्थित हिमाचल निकेतन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे छः माह के भीतर

पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 145 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हो रहे इस बहुउद्देशीय भवन में 107 कमरे, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट व मल्टीपर्पज हॉल, मीटिंग हॉल, डॉर्मिटरी, पार्किंग, गार्डन और ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि यह निकेतन उपचार, शिक्षा और अन्य कार्यों से दिल्ली आने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और उन्हें बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करेगा।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी और मरीज दिल्ली आते हैं और हिमाचल निकेतन उन्हें सुविधाजनक ठहराव उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग देवेश कुमार ने परियोजना की प्रगति की जानकारी दी।

निरीक्षण के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार, प्रमुख आवासीय आयुक्त अजय यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

नड्डा से राज्य के मुद्दे प्रभावी ढंग से उठाने की मांग

1,500 करोड़ का आपदा पैकेज अब तक नहीं मिला

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार पर राज्य की

उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश से होने के नाते राज्य के मुद्दों को केंद्र के समक्ष प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा।

संयुक्त ब्यान में मंत्रियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों की राहत और पुनर्वास के लिए घोषित 1,500 करोड़ रुपये का पैकेज कई महीने बीतने के बावजूद राज्य को नहीं मिला है। इसके अलावा, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के तहत जमा 9,200 करोड़ रुपये की राशि भी केंद्र सरकार ने रोक रखी है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू किए जाने के बाद केंद्र ने उधारी सीमा में 1,600 करोड़ रुपये की कटौती की, जिससे बीते तीन वर्षों में राज्य को कुल 4,800 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है।

मंत्रियों ने कहा कि केंद्र की ओर से सहायता के आंकड़ों को लेकर किए जा रहे दावों के बावजूद, राज्य के हिस्से की राशि रोके जाने से हिमाचल पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने राज्य की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी में कटौती के साथ-साथ ऋण सीमा भी लगातार घटाई गई है।

ब्यान के अनुसार, वर्ष 2021-22 में 10,949 करोड़ रुपये की राज्य की ऋण सीमा घटकर 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपये रह गई है। राज्य की अधिकांश उधारी ब्याज भुगतान में ही खर्च हो रही है, जबकि 1,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी की सुविधा भी वापस ले ली गई है।

मंत्रियों ने बताया कि वर्ष 2023 के मानसून के दौरान हुए नुकसान का केंद्रीय टीम ने 9,000 से 9,500 करोड़ रुपये का आकलन किया था। इसके तहत राज्य सरकार ने पीडीएनए के

अंतर्गत पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण के लिए 9,042 करोड़ रुपये का दावा प्रस्तुत किया है, लेकिन अब तक इस मद में कोई सहायता नहीं मिली है। साथ ही, घोषित 1,500 करोड़ रुपये के अलग पैकेज का भी इंतजार है।

उन्होंने कहा कि केंद्र से विशेष सहायता न मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से आपदा प्रभावित लोगों को 4,500 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की है। अंत में मंत्रियों ने जगत प्रकाश नड्डा से आग्रह किया कि वे हस्तक्षेप कर हिमाचल प्रदेश के हित में इन लंबित मामलों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाएं।

बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड ने 3,835 लाभार्थियों में बांटे 14.17 करोड़

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) ने अब तक 3,835 लाभार्थियों को 14.17 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। इनमें से 9.28 करोड़ रुपये शिक्षा सहायता योजनाओं के तहत वितरित किए गए हैं। यह

जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बोर्ड की 53वीं निदेशक मंडल बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

बैठक में बोर्ड द्वारा जिला मंडी के बलद्वाड़ा (भांबला) में नया उप-कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक खातों को स्वीकृति प्रदान की गई और लंबित दावों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

अध्यक्ष ने श्रमिकों के क्लेम फॉर्म और ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश देते हुए कहा कि पात्र निर्माण कामगारों को समय पर लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित दावों का शीघ्र निपटारा करने और आवश्यक औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिये।

नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि प्रदेशभर में निर्माण कामगारों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और उत्थान के लिए बोर्ड की प्रतिबद्धता के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रमिक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

बैठक में बोर्ड के गैर-आधिकारिक सदस्य रविंद्र सिंह रवि, भूपेंद्र सिंह, जे.सी. चौहान और प्रदीप कुमार के अलावा विशेष सचिव (वित्त) विजय वर्धन, सचिव-कम-सीईओ राजीव कुमार तथा अतिरिक्त सचिव (विधि) आर.एस. तोमर भी उपस्थित रहे।

2032 तक हर विधानसभा क्षेत्र में उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने समग्र शिक्षा निदेशालय में विद्या समीक्षा केंद्र, शिक्षा दीर्घा, कार्यक्रम प्रबंधन स्टूडियो-सह

-सम्मेलन क्षेत्र, नये सम्मेलन कक्ष तथा आधुनिक केंद्रीय ताप व्यवस्था का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं प्रदेश में डिजिटल शिक्षा प्रबंधन के नए युग की शुरुआत करेंगी और शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाएंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते तीन वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में किये गये सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा गुणवत्ता आकलन में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान से पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से शिक्षण, मूल्यांकन और विद्यालय संचालन से संबंधित वास्तविक समय का डाटा उपलब्ध होगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनेगी।

उन्होंने घोषणा की कि आगामी शैक्षणिक सत्र से प्री-नर्सरी से 12वीं कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल परिसर में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही शिक्षा विभाग में अस्थायी व स्थायी भर्तियां की जाएंगी और प्राथमिक विद्यालयों में खेल प्रतियोगिताएं शुरू होंगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'संकल्प वर्कबुक' का विमोचन किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की साक्षरता दर 99.30 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और विभिन्न नवाचारों से शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है।

मंडी में लाभार्थियों को करोड़ों की सहायता वितरित

शिमला/शैल। मंडी में आयोजित जन संकल्प सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित की।

राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना के 401 लाभार्थियों के खातों में 50.63 लाख रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे गए, जबकि सात जिलों के आपदा प्रभावितों को 51 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि प्रदान की गई। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 25 लाभार्थियों को ई-टैक्सी की चाबियां दी गई और 21 युवाओं को विदेश रोजगार के लिए टिकट और वीजा उपलब्ध कराए गए।

मत्स्य पालन, मधु उत्पादन और पुष्प क्रांति योजनाओं के अंतर्गत भी लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई। किन्नौर के पांच व्यक्तियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत भू-स्वामित्व पट्टे जारी किए गए।

श्री निवास रामानुजन डिजिटल योजना के तहत 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तर के 9,350 मेधावी छात्रों को ई-वाउचर प्रदान किए गए, जिससे वे अपनी पसंद के डिजिटल गैजेट प्राप्त कर सकेंगे।

मानवता की महानता मानव होने में नहीं, बल्कि मानवीय होने में है।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

मोदी सत्ता पर उठते सवाल

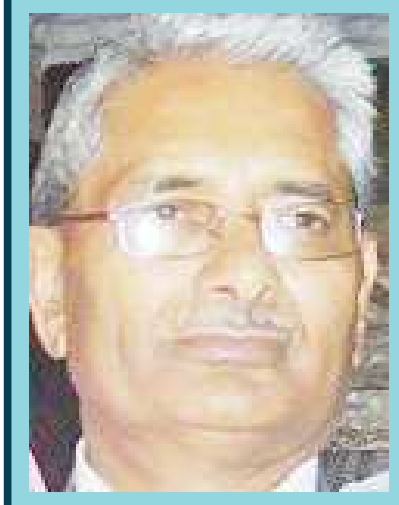

केन्द्र में जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ था उस समय इस परिवर्तन के सबसे बड़े कारक भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ खड़े हुये अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव के आन्दोलन रहे हैं। इन आन्दोलनों ने यह स्थापित कर दिया था कि देश की जनता भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकती है। यह आन्दोलन आर एस एस से पोषित संचालित और नियंत्रित थे। लेकिन देश के आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं था कि इन आन्दोलनों की रणनीति का नियंत्रक कौन था। आम आदमी के लिये भ्रष्टाचार और काले धन पर उस समय परोसे गये आंकड़े ही सब कुछ थे। इसी आन्दोलन का प्रभाव था कि कांग्रेस समेत हर दल के नेता भाजपा में शामिल हो गये। उस समय भाजपा ने देश की जनता से पांच वर्ष का कार्यकाल मांगा था अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिये। लेकिन आज भाजपा – मोदी का सत्ता में तीसरा कार्यकाल चल रहा है। अब तक के कार्यकाल पर अगर नजर डालें तो यह सामने आता है कि भ्रष्टाचार के नाम पर ईडी,सीबीआई, आयकर और एनआईए सभी एजैन्सियां अति सक्रिय हैं। परन्तु उनके बनाये हुये कितने मामलों में दोष प्रमाणित होकर दोषी को सजा मिल पायी है तो शायद यह आंकड़ा अभी तक पांच प्रतिश्त तक नहीं पहुंच पाया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय से जिस तरह से वरिष्ठ अधिकारियों को निकाला गया उससे बहुत कुछ व्यावहारिक रूप से सामने आ जाता है। अब तक मोदी सरकार अपने कितने चुनावी वादों को पूरा कर पायी है तो शायद सुक्खू सरकार का आंकड़ा मोदी के आंकड़ों से बेहतर होगा। यही नहीं डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। इससे अर्थव्यवस्था का व्यावहारिक पक्ष सामने आ जाता है। कितने किसानों की आय दोगुनी हो पायी है यह आंकड़ा आज तक जारी नहीं हो सका है। मोदी सरकार ने हर चुनाव में नये नैरेटिव उछाले हैं। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास आज बुलडोजर न्याय तक पहुंच गया है। दो करोड़ नौकरियां जुमला बनकर रह गया है।

लेकिन यह सब होते हुये भी लगातार चुनावी जीत हासिल की है। इस बार के चुनाव में भाजपा अपने ही दम पर सरकार नहीं बना पायी है और इसी से स्पष्ट हो जाता है कि देश की जनता इस जीत के जादू को समझने लग पड़ी है। इस समझ में यह सामने आ गया है कि यह जीत चुनाव आयोग के सहयोग के कारण हो रही है। वोट चोरी कितने सुनियोजित तरीके से की जा रही है इसके दस्तावेजी प्रमाण सामने आ चुके हैं। चुनाव आयोग वोट चोरी के आरोपों पर जिस तरह के तर्क सामने रख रहा है उससे आयोग की निष्पक्षता पूरी तरह प्रश्नित हो गयी है। एसआईआर का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में जिस तरह से चल रहा है उससे शीर्ष अदालत पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लग पड़े हैं। चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय दो शीर्ष संवैधानिक स्वायत संस्थान हैं जो सिर्फ संविधान के प्रावधानों से संचालित होते हैं। लेकिन पहली बार देश का विश्वास इन संस्थानों पर प्रश्नित होने लगा है। उनकी निष्पक्षता पर उठते सन्देह कालान्तर में लोकतंत्र के लिये घातक प्रमाणित होंगे यह तय है। सरकार की मंशा पर लगातार सवाल खड़े होते जा रहे हैं। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि सरकार येन केन प्रकारेण हिन्दू राष्ट्र के ऐजैण्डे पर चल निकली है। इसी ऐजैण्डे के लिये संविधान में बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसी ऐजैण्डे के तहत सार्वजनिक संसाधनों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इसी के तहत यह पहली सरकार है जिनके कार्यकाल में कोई भी नया सार्वजनिक संस्थान स्थापित नहीं हुआ है। अब जब वोट चोरी का सच देश के हर कोने तक पहुंच गया है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि अब इस मुद्दे को जनान्दोलन बनने से हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा भी नहीं रोक पायेगी। क्योंकि यह देश बहुधर्मी और बहुभाषी है। इसमें एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताकर सत्ता नहीं चलाई जा सकती। अभी वन्दे मातरम की चर्चा के दौरान जो दस्तावेजी प्रमाण संसद के पटल पर आये हैं वह देर सवेर पढ़े जायेंगे और यह सच सामने आयेगा कि इतिहास को इतिहास लेखन प्रकोष्ठों के लेखन से बदला नहीं जा सकता। देश की स्वतंत्रता में जिन लोगों का योगदान रहा है उसे बदला नहीं जा सकता यह एक स्थापित सच है आज मोदी सत्ता पर उठते सवाल इसी कारण से गंभीर होते जा रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया की हालिया घटना को पवित्र कुरान की नजरों से सही नहीं ठहराया जा सकता

गौतम चौधरी

अभी हाल ही की बात है। ऑस्ट्रेलिया स्थित सिडनी के एक समुद्री किनारे पर यहूदी समुदाय के लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्योहार मना रहे थे, उसी बीच दो आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना में कम से कम 12 लोगों की जान चली गयी। इस घटना को एक बार फिर से इस्लाम के साथ जोड़ा जा रहा है। कुछ मौकापरस्थ लोग इसे इस्लामिक आतंकवाद की भी संज्ञा देने लगे हैं लेकिन वे इस बात को नजरअन्दाज कर रहे हैं कि जब दो सिरफिरे अंधाधुंध गोलिया वर्षा रहे थे, ठीक उसी वक्त एक निहत्था व्यक्ति आतंकवादियों से भिड़ गया और उसकी बंदूक छीन ली। अगर वह शख्स आतंकवादियों से नहीं जूझता तो और कई लोग मारे जाते। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उस शख्स का नाम अहमद अल – अहमद है। अहमद भी अरबी मूल का है और वह फल बेचने का व्यवसाय करता है। 43 साल के अहमद के दो बच्चे हैं और वह भी मुसलमान है। अब इस घटना को इस्लामिक आतंकवाद कहना कितना जायज होगा?

आइए, इस पूरे मामले को कुरान के नजरीए से देखते हैं। ''कुरान 2:62, 5:69, 2:112 और 3:113 – 115 से यह बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि अल्लाह किसी खास धार्मिक समूह का पक्ष नहीं लेता। वह हर उस इंसान से प्यार करता है जो अल्लाह पर विश्वास करता है, आखिरत को मानता है और अच्छे काम करता है।'' इसी तरह, ''सूरह यूनुस, आयत 32 की व्याख्या कभी किसी मुस्लिम विद्वान ने उस तरह से नहीं दी। इसका प्रैक्टिकल प्रदर्शन और व्याख्या फ्रांस के एक ईसाई डॉक्टर, डॉ. मौरिस ने 1975 में की थी। इसी तरह, सूरह फुस्सिलात, आयत 53 की व्याख्या भी वैज्ञानिकों ने दी थी। पवित्र ग्रंथ कुरान सिर्फ़ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं उतारी गई है। यह पूरी इंसानियत के लिए एक यूनिवर्सल और हमेशा रहने वाला मार्गदर्शन है लेकिन मुसलमानों के कुछ ठेकेदारों ने इसे सीमाओं में बांध दिया। जब लोग इस पर ज्यादा सोचते हैं, तो वे कुरान से इस्लामी राजनीतिक शासन साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। यह गलत है। कुरान तो मानवता के उन्नयन की पवित्र किताब है। अगर ये आयतें नहीं होतीं, तो कुरान इस धरती पर रहने वाले हर इंसान के लिए मार्गदर्शन का ज़रिया नहीं रहता। पवित्र ग्रंथ के इतने साफ़ मार्गदर्शन के बावजूद, कुछ सिरफिरे लोगों ने खुद को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी जैसे ग्रुप में बांट लिया और ऐसा करके, उन्होंने खुद को बनाने वाले का असली इरादा खो दिया।

बरेलवी फिरके के मुफ्ती मौलाना तुफैल खान कादिरी साहब फरमाते हैं, ''पवित्र कुरान में कई ऐसी आयते नाजिल हुई है, जिसमें मानवता की रक्षा का संकल्प दोहराया गया है। एक आयत तो साफ संदेश देता है कि जिसने निर्दोष की हत्या की मानों उससे पूरी मानवता का कत्ल कर दिया और जिसने किसी निर्दोष की रक्षा की मानों उसने पूरी मानवता की रक्षा की हो।'' कादिरी साहब कहते हैं कि ''ऑस्ट्रेलिया में हुए यहूदियों पर हमले को यदि कुरान की नजरों से देखें तो यह निहायत नाजायज है। इससे मुसलमानों का कोई सरोकार नहीं है। जबकि अहमद अल – अहमद न केवल मानवता का नायक है अपितु इस्लाम का भी गाजी है। अहमद अल – अहमद असल में धर्म का रक्षक और इस्लाम का सच्चा सिपाही है। इस्लाम हमें यही सिखाता है।''

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बीते रविवार शाम को अंधाधुंध फायरिंग में 12 लोगों की जानें गई। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को निशाना बनाकर हमला करने वाले दो में से एक का संबंध पाकिस्तान से है। दो हमलावरों में से एक मारा गया है, जबकि एक को घायल हालत में गिरफ्तार किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि दोनों हमलावर पिता – पुत्र हैं। सूत्रों के अनुसार, जांचकर्ताओं ने संदिग्ध की पहचान न्यू साउथ वेल्स की अल – मुराद इंस्टीटयूट के छात्र के रूप में की है। यह संस्थान अरबी और कुरान की शिक्षा देता है। जांच अधिकारी उसकी शैक्षिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की जांच कर रहे हैं। फिलहाल उसके संस्थान का आतंकी हमले से कोई संबंध नहीं मिला है। हमलावर, नवीद अकरम ने सिडनी में सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद में हैमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। उसने अल – मुराद इंस्टीटयूट में भी पढ़ाई की, जहां उसे एक आदर्श छात्र बताया गया था। द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने बताया है कि उसने हाल ही में अपनी नौकरी खो दी थी।

मीडिया रिपोर्ट और दावों पर ध्यान दें तो हमलावर निःसंदेह मुसलमान है। उसने मुस्लिम शिक्षा भी ग्रहण कर रखी थी। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान की पढ़ाई कर चुका था लेकिन आतंकवादियों से बिना किसी हथियार के भिड़ने वाला शख्स का कोई धार्मिक पृष्ठभूमि सामने नहीं आया है। उसका नाम अरबी है इसलिए लोगों का मानना है कि वह भी मुसलमान ही है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, जो धार्मिक पुस्तकों की व्याख्या निजी हितों के लिए कर रहे हैं। इस्लामिक विद्वानों और समझदार संस्थाओं को इसपर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। इजरायल में हो रही घटना, या फिर फिलिस्तीनियों के साथ हो रहे अन्याय को यहूदियों पर आक्रमण कर बदला लेना इसे किसी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता है। यह न तो मानवता के लिए ठीक है और न ही इस्लाम इसकी इजाजत देता है। इससे इस्लाम का भला नहीं होगा। उलट इस्लाम के खिलाफ जो षडयंत्र चल रहे है, उसे बल मिलेगा।

इस प्रकार के सिरफिरे लोग भारत में भी हैं। हमारा देश लगातार इस प्रकार के आतंकवाद से जूझ रहा है। इसका एक वैश्विक रूप तैयार हो गया है। इस प्रकार के मानस को तैयार करने में कौन लोग जिम्मेदार हैं, उस पर सत्ता और शासन से ज्यादा मुसलमानों को नजर रखने की जरूरत है। इधर के दिनों में अरब के कई मुस्लिम देश अपने आप को बदलने लगे हैं, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक राष्ट्र नकारात्मक मानसिकता को लगातार हवा दे रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान नेतृत्व भी फिलहाल इसी दिशा में काम कर रहा है। इसे संभालने की जरूरत है और ईमान वाले इसे बेहतर समझ समझ सकते हैं।

आदिवासी महिलाओं की भूमिका और नेतृत्व

– सावित्री ठाकुर –
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
भारत सरकार

भारत विविध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन-पद्धतियों वाला समृद्ध देश है, और इसमें अनुसूचित जनजातियों की आबादी 10.45 करोड़ से अधिक है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है। यह केवल जनसंख्या का आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की जीवंत, प्राचीन और बहुविध सांस्कृतिक धरोहर का अद्वितीय स्वरूप है। यह समुदाय न केवल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संवाहक रहा है, बल्कि अपनी समृद्ध परंपराओं, भाषा-भाषाई विविधता और मौलिक ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक पहचान को निर्मित करता रहा है। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इनके पराक्रम, बुद्धिमत्ता और प्रकृति से गहरे संबंध का उल्लेख मिलता है।

फिर भी, लंबे समय तक आदिवासी समाज को मुख्यधारा के विकास से दूर रखा गया। उन्हें एक जीवित संस्कृति के संरक्षक के रूप में तो देखा गया, पर समान भागीदार के रूप में नहीं। विशेषकर आदिवासी महिलाओं के नेतृत्व, कौशल, सामाजिक समझ और समुदाय निर्माण में उनकी भूमिका को लंबे समय तक वह मान्यता नहीं मिली, जिसकी वे वास्तविक हकदार थीं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस सोच और व्यवस्था में स्पष्टत था उद्देश्य पूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है। सरकार ने टोकनिज़्म (प्रतीकात्मक पहल) से आगे बढ़कर टार्गेटेड एम्पावरमेंट (लक्ष्य आधारित सशक्तिकरण) की नीति अपनाई है। जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास के प्रति यह प्रतिबद्धता इस बात का प्रमाण है कि भारत की विकास यात्रा में अब कोई भी समुदाय पीछे न रह जाए। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का मंत्र इसी समावेशी दृष्टि का सशक्त उदाहरण बन चुका है।

इसी प्रतिबद्धता का प्रभाव बजट आवंटन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जनजातीय समुदायों के विकास हेतु कुल बजट 2024-25 में 10,237.33 करोड़ रूपये से बढ़कर 2025-26 में 14,925.81 करोड़ रूपये हो गया है, जो 45.79% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यदि दीर्घकालीन दृष्टि से देखें, तो 2014-15 में 4,497.96 करोड़ रूपये के बजट के मुकाबले यह राशि पहले 2021-22 में 7,411 करोड़ रूपये तक पहुंची और अब यह वृद्धि 231.83% तक पहुंच गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए बढ़े हुए आवंटन से स्पष्ट है कि अब आदिवासी समुदाय, खासकर महिलाएं, विकास की यात्रा में केवल लाभार्थी नहीं बल्कि नेतृत्वकारी भूमिका में हैं।

भारत की आदिवासी महिलाएं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की धुरी रही हैं। वे जल, जंगल और जमीन से जुड़ी पारंपरिक जीवन व्यवस्थाओं की संरक्षक हैं और सामुदायिक निर्णय, संसाधन प्रबंधन और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज यह भूमिका केवल पारिवारिक और सामुदायिक स्तर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि शासन व्यवस्था से लेकर नीति निर्माण तक दिखाई दे रही है। इस परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली प्रतीक यह है कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आसीन हैं।

सरकार ने आदिवासी महिलाओं के सामाजिक-सांस्कृतिक सशक्तिकरण, आर्थिक उत्थान एवं उनके नेतृत्व को संस्थागत आधार प्रदान करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे विकास केवल सुविधाओं का विस्तार न होकर, सम्मान, पहचान और आत्मनिर्भरता को भी सुनिश्चित करे। इनमें आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए 2 लाख रूपये तक का ऋण मात्र 4% ब्याज दर पर प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे हस्तशिल्प, कृषि-आधारित कार्य, बांस उत्पाद, पशुपालन, प्रसंस्करण एवं सेवा क्षेत्र में उद्यमशीलता विकसित कर रही हैं।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए शुरू किया गया प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) इन समुदायों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचा रहा है। यह अभियान 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 75 PVTG समुदायों के उन इलाकों में विकास सुनिश्चित कर रहा है, जो लंबे समय से मुख्यधारा से दूर रहे हैं। लगभग 24,104 करोड रूपये के निवेश के साथ PM-JANMAN आवास, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, शिक्षा, सड़क संपर्क और सतत आजीविका जैसे क्षेत्रें में समग्र सुधार ला रहा है।

इसके अतिरिक्त, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) आदिवासी बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे उनके कौशल विकास के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। साथ ही, छात्रवृत्ति योजनाओं ने विशेषरूप से बालिकाओं में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

DAY-NRLM ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आदिवासी महिलाओं की वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता, सामूहिक उत्पादन, विपणन और आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ किया है। वहीं सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान ने गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर और मातृ-स्वास्थ्य संकेतकों को सुधारने का कार्य किया हैं।

पेसा (PESA) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के माध्यम से पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन की शक्ति दी गई है। इस कानून ने पंचायत और ग्राम सभा में महिला भागीदारी को संरचनात्मक स्तर पर सुनिश्चित किया है, जिसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए विशेष नेतृत्व प्रशिक्षण मॉडयूल विकसित किए गए हैं।

आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभरा है। इस अभियान के तहत 20 लाख से अधिक परिवर्तनकारी प्रतिनिधियों (Change Agents), जिनमें महिला स्वयं-सहायता समूहों की सदस्याएं, युवा और स्थानीय अधिकारी शामिल हैं, को शासन, सेवा वितरण और सामुदायिक सशक्तिकरण में स्थानीय नेतृत्व के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। अभियान का लक्ष्य '1 लाख जनजातीय गांव- विज़न 2030' के माध्यम से सहभागी शासन प्रणाली को मजबूत करना है, जिसमें महिलाओं की केंद्रीय भूमिका सुनिश्चित की गई है। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने भी इस अभियान की सराहना की है और कहा है कि जमीनी स्तर पर आदिवासी नेतृत्व ही 'विकसितभारत@2047' की आधारशिला है। आज अनेक जनजातीय बहुल गांवों में महिलाएं ग्राम संस्थाओं की अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व कर रही हैं, स्वयं-सहायता समूहों का संचालन कर रही हैं, शासन प्रयोगशालाओं में परिवर्तनकारी नेतृत्व निभा रही हैं और अपने समुदाय को आजीविका एवं विकास योजनाओं से जोड़ रही हैं।

साथ ही, वर्ष 2024 में शुरू 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के तहत 63,000 से अधिक जन जातीय बहुल गांवों में समग्र विकास के लिए 79,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका एक मुख्य आधार ग्राम समितियों में महिलाओं की प्रत्यक्ष नेतृत्व भूमिका को मजबूत करना है।

भारत की विकास यात्रा में आदिवासी महिलाओं की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि वे अब केवल सहभागी नहीं, बल्कि परिवर्तन की अग्रणी शक्ति बन रही हैं। अब हमारा ध्यान इस बात पर है कि जमीनी स्तर पर उनके नेतृत्व को कैसे और मज़बूत बनाया जाए। इसी उद्देश्य से स्थानीय समुदायों में महिला नेतृत्व प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि अधिकाधिक महिलाएं प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

वन आधारित आजीविका और हस्त-उद्यमों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ना हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में है, जिससे उनके कार्य का मूल्य और सम्मान दोनों बढ़ें। स्वयं सहायता समूहों और आजीविका समूहों के माध्यम से महिलाएं समाज में सकारात्मक परिवर्तन की सशक्त वाहक बन रही हैं। इस दिशा में डिजिटल साक्षरता और वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण को और व्यापक रूप से लागू किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक महिला आत्मनिर्भर बन सके।

साथ ही, आदिवासी बालिकाओं की उच्च शिक्षा और कौशल विकास तक पहुंच को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ भविष्य के नेतृत्व पदों तक आगे बढ़ सकें। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है- आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण केवल सामाजिक संवेदना का विषय नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक विस्तार, सतत विकास और समावेशी प्रगति की सबसे मज़बूत नींव है।

सरकाघाट में गरीब परिवार की बेटियों का सहारा बन रही है मुख्यमंत्री शगुन योजना

बेटी की शादी पर बीपीएल परिवार को शगुन के रूप में दी जा रही 31 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में प्रदेश सरकार कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए वचनबद्ध है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित प्रदेश सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चला रखी है जो समाज के कमजोर तबकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता दर्शाती हैं। इसी कड़ी में वर्तमान सरकार की शगुन योजना सरकाघाट क्षेत्र के बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए मददगार साबित हो रही है।

इस योजना के तहत प्रदेश सरकार बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी में 31 हजार रुपए की राशि शगुन के रूप में प्रदान कर उनकी आर्थिक सहायता कर रही है।

आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में तैनात संबंधित सीडीपीओ कार्यालय में किया जा रहा है। लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक और वह हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए। इस योजना के लिए लड़की के माता-पिता , अभिभावक या लड़की स्वयं भी आवेदन कर सकती है।

सरकाघाट के गांव खनोट तहसील बलद्वाड़ा से संबंध रखने वाली तनु कुमारी की शादी गांव मनवाणा में हुई है। वे बताती हैं कि मेरी शादी पिछले साल नवम्बर 2024 में हुई। तो हमें स्थानीय आंगनबाड़ी वर्कर से पता चला कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली बेटियों की शादी पर 31 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। इस पर मेरे परिवार वालों ने भी इस योजना के लिए आवेदन किया। शादी के पांच महीने बाद 31 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता राशि शगुन के रूप में सरकार से प्राप्त हुई। मैं और मेरा परिवार प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए इतनी अच्छी योजनाएं चला रखी हैं।

तनु कुमारी की माता रेखा देवी ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद करते हुए कहा कि गरीब परिवार की बेटियों के लिए यह एक अच्छी योजना चलाई है।

धर्मपुर ब्लॉक से संबंध रखने वाली सुनीता देवी पत्नी दिनेश कुमार गांव सरौन बताती हैं कि उनकी बेटी आंचल चौहान की शादी पिछले साल अक्टूबर, 2024 में हुई थी। उसी समय हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शगुन योजना का पता चला था। जिसके बाद हमने भी इस योजना के लिए फॉर्म भरे और बेटी की शादी के चार महीने बाद हमें 31 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदेश सरकार से शगुन के रूप में प्राप्त हुई। हम मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हैं कि उनकी सरकार गरीब परिवार की इतनी सहायता कर रही है।

अन्य लाभार्थी वंदना देवी पत्नी राज कुमार गांव अपर बरोट सरकाघाट बताती हैं कि उनकी बेटी नेहा की शादी पिछले साल नवम्बर, 2024 में हुई थीं। उस समय हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पता चला कि सरकार ने मुख्यमंत्री शगुन योजना चला रखी है जिसमें बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप 31 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। तो हमने भी इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकाघाट सीडीपीओ कार्यालय में आवेदन किया था। शादी के तीन महीने बाद हमें 31 हजार रुपए प्राप्त हुए। इन सबके लिए मैं और मेरा परिवार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने गरीब परिवारों के उत्थान के लिए इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं।

मुख्यमंत्री ने एपीएआर सॉफ्टवेयर विकास की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) सॉफ्टवेयर के विकास कार्य की प्रगति की समीक्षा की। यह सॉफ्टवेयर डिजिटल

टेक्नोलॉजीज एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए पारदर्शी और पूर्णत: डिजिटल प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली लागू करना है।

बैठक में बताया गया कि एपीएआर पोर्टल के माध्यम से एपीएआर और वार्षिक कार्य योजनाओं की एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग सुव्यवस्थित डिजिटल वर्कफ्लो के तहत होगी, जिससे निष्पक्षता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। एपीएआर की शुरुआत वार्षिक कार्य योजना तथा निर्धारित गुणात्मक और मात्रात्मक लक्ष्यों के आधार पर की जाएगी, जिनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन का प्रावधान भी होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' के सभी कर्मचारियों के लिए एक समान और मानकीकृत एपीएआर प्रारूप लागू किया जाएगा। प्रणाली में रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारियों की ऑनलाइन पहचान और अनुमोदन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम तीन माह की अवधि के साथ एक से अधिक एपीएआर शुरू किए जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने सॉफ्टवेयर को समयबद्ध रूप से पूरा करने और इसे उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने पर जोर देते हुए कहा कि यह पहल प्रदर्शन-आधारित शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल, विधायक सुरेश कुमार तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बेटी आस्था के विवाह की शुभकामनाएं देने उपमुख्यमंत्री के आवास पहुंचे जे.पी. नड्डा

शिमला/शैल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा

अपने शिमला प्रवास के दौरान छोटा शिमला स्थित उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आवास पहुंचे। नड्डा ने उपमुख्यमंत्री की इकलौती बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री के विवाह अवसर पर परिवार को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं।

अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच समय निकालकर नड्डा का उपमुख्यमंत्री के घर पहुंचना राजनीतिक सौहार्द और आपसी सम्मान की मिसाल माना जा रहा है। मुलाकात के दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं ने राजनीतिक अनुभवों, पुरानी स्मृतियों और निजी विषयों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा की।

इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उपमुख्यमंत्री की दिवंगत पत्नी, प्रो. सिमी अग्निहोत्री को भी श्रद्धापूर्वक याद किया और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं।

दोनों नेताओं की मुलाकात ने हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति में स्थापित आपसी सम्मान और शिष्टाचार की परंपरा को एक बार फिर मजबूत संदेश दिया।

झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले टोंग लेन स्कूल के बच्चों का सपना हुआ साकार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने एक बार फिर अपने संवेदनशील और मानवीय व्यक्तित्व

का परिचय दिया है। धर्मशाला के सराह क्षेत्र स्थित टोंग लेन स्कूल में अध्ययनरत झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले 160 बच्चों को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को स्टेडियम में बैठकर देखने का अवसर मिला। यह अवसर मुख्यमंत्री द्वारा अपने हालिया धर्मशाला दौरे के दौरान बच्चों से किए गये वायदे के अनुरूप प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री की इस भावनात्मक पहल से बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। सीमित संसाधनों में जीवन यापन करने वाले इन बच्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को प्रत्यक्ष देखना किसी सपने के साकार होने जैसा रहा। मैच के दौरान बच्चों का उत्साह, उमंग और रोमांच देखते ही बनता था।

बच्चों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने पहली बार इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन को नजदीक से देखा है, जिसे वे जीवनभर याद रखेंगे। विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों ने भी मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास समाज के वंचित वर्ग के बच्चों में आत्मविश्वास जगाने और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने बताया कि यह पहला अवसर है जब टोंग लेन स्कूल के बच्चे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम, धर्मशाला में किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैच देखने पहुंचे हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में धर्मशाला में आयोजित शीतकालीन सत्र के दौरान सुबह की सैर के समय मुख्यमंत्री ने टोंग लेन संस्था के होस्टल का दौरा किया था। इस दौरान बच्चों से बातचीत में उन्होंने उन्हें क्रिकेट मैच दिखाने का वायदा किया था, जिसे अब उनके निर्देश पर पूरा किया गया।

उल्लेखनीय है कि धर्मशाला और आसपास की झुग्गियों में बाहरी राज्यों से आये मजदूर परिवार निवास करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। इन परिवारों के बच्चों को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। टोंग लेन संस्था के माध्यम से ये बच्चे शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को संवार रहे हैं और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की इस पहल ने उनके सपनों को नई उड़ान दी है।

चमेरा चरण-III प्रभावितों के पुनर्वास पर उपायुक्त ने दिए निर्णायक निर्देश

शिमला/शैल। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में एनएचपीसी की चमेरा चरण-III विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों के राहत एवं पुनर्वास मामलों की समीक्षा को लेकर निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उपायुक्त ने परियोजना प्रभावितों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुनर्वास नीति के तहत रिक्त पदों के लिए संबंधित पंचायतों से पात्र व्यक्तियों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने और संविदा कर्मचारियों की आगामी सेवानिवृत्ति सूची प्रशासन को सौंपने को कहा।

मुचका गांव के भूस्खलन प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर विशेष जोर देते हुए उपायुक्त ने सुरक्षित वैकल्पिक आवास स्थल चिन्हित करने तथा दिव्यांग, असहाय और विधवा सदस्यों को प्रतिमाह एक हजार रुपये पेंशन देने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना क्षेत्रों में कूड़ा निष्पादन संयंत्र स्थापित करने, ठोस कचरे के वैज्ञानिक निपटान और स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक चिकित्सक उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में परियोजना प्रबंधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

हिमाचल में जियोडेटिक एसेट्स रजिस्टर और मैप जारी आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना में मिलेगा लाभ

शिमला/शैल। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व के.के. पंत ने भू-स्थानिक निदेशालय, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल

प्रदेश और चंडीगढ़ द्वारा तैयार जियोडेटिक एसेट्स रजिस्टर और जियोडेटिक मैप का विमोचन किया। यह प्रस्तुति निदेशक गौरव कुमार सिंह ने दी।

रजिस्टर में प्रदेश की जियोडेटिक अधोसंरचना को छह प्रमुख श्रेणियों में वगीकृत किया गया है, जिनमें सतत संचालन संदर्भ स्टेशन, ग्रेट ट्रिग्नोमैट्रिक सर्वे स्टेशन, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स, मैग्नेटिक रेफ्रेंस स्टेशन, ग्रैविटी रेफ्रेंस स्टेशन और लेवलिंग बेंचमार्क शामिल हैं।

विमोचन समारोह के दौरान के. के. पंत ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक संवेदनशीलता को देखते हुए यह रजिस्टर और मैप आपदा न्यूनीकरण योजनाओं में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है, ऐसे में जियोडेटिक डेटा वैज्ञानिक और प्रभावी निर्णय लेने में मददगार सिद्ध होगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण-अनुकूल और सुनियोजित अधोसंरचना को बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में जियोडेटिक रजिस्टर न सिर्फ अनुसंधान को बल देगा, बल्कि भविष्य की योजना और निर्माण कार्यों के लिए भी मार्गदर्शक साबित होगा। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग आधुनिक तकनीकों का तेजी से उपयोग कर रहा है। गांवों के नक्शे एवं भू-नक्शों को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे स्वामित्व और भू-नक्शा परियोजनाओं में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित हुई है। कार्यक्रम में विशेष सचिव डी.सी. राणा सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

एंटी-चिट्टा अभियान के तहत 20 दवा निर्माण इकाइयों पर छापेमारी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू द्वारा 15 नवम्बर को शुरू की गई प्रदेशव्यापी एंटी-चिट्टा ड्राइव के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस और औषधि विभाग ने संयुक्त रूप से राज्यभर में 20 दवा निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया। अभियान का उद्देश्य प्रतिबंधित दवाओं के अवैध निर्माण और तस्करी पर रोक लगाना है।

निरीक्षण के दौरान बंद, निलंबित और समर्पित लाइसेंस वाली इकाइयों में लाइसेंस, दस्तावेज, स्टॉक और उत्पादन क्षेत्रों की जांच की गई तथा गोदामों की तलाशी ली गई। खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह कारवाई की गई, जिसमें आशंका थी कि बंद पड़ी इकाइयों का दुरुपयोग अवैध दवा निर्माण में हो सकता है।

छ: जिलों में किए गए इस अभियान में ऊना और बिलासपुर में 22, सोलन में 4, सिरमौर में 1, पुलिस जिला नूरपुर में 1 और पुलिस जिला बद्दी में 10 इकाइयों की जांच की गई। इस अभियान में चार इकाइयों में अनियमितताएं पायी गयी, जिनके खिलाफ कानूनी कारवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ राज्य की 'शून्य सहिष्णुता' नीति के तहत दवा निर्माण इकाइयों में किसी भी तरह के दुरुपयोग, अवैध उत्पादन या तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने साफ किया कि नशामुक्त हिमाचल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी।

गारंटियों का हिसाब छोड़ रैलियों में व्यस्त सरकार: जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जनता को दी गई

गारंटियों का हिसाब न देने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि झूठी गारंटियों और घोषणापत्र के नाम पर जनादेश हासिल करने वाली कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता को जवाब देने के बजाये दिल्ली और देशभर में रैलियां कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जहां भी इस तरह के अभियानों में जाते हैं, वहां केवल भ्रामक बयान देकर लोगों को गुमराह किया जाता है, लेकिन अब देश की जनता कांग्रेस की वास्तविकता समझ चुकी है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोग सरकार की विफलताओं से जूझ रहे हैं, जबकि पूरी सरकार दिल्ली में पार्टी आलाकमान को खुश करने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व लगातार संवैधानिक संस्थाओं, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निराधार आरोप लगाता रहा है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए को समर्थन देने वाले मतदाताओं पर सवाल उठाना भी जनता का अपमान है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के वरिष्ठ नेता प्रशासनिक जिम्मेदारियों को छोड़कर चुनावी अभियानों में शामिल हुए हों। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के समय सदन में चर्चा और राहत कार्यों की समीक्षा के बजाये भी सरकार के नेता रैलियों में व्यस्त रहे, जबकि आपदा प्रभावित आज भी सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

जयराम ठाकुर ने सरकार पर अंतर्कलह और प्रशासनिक शिथिलता का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायकों और मंत्रियों की विवशता, अधिकारियों और करीबी लोगों की मनमानी के आगे व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली सरकार की कार्यप्रणाली चरमराई हुई है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए निर्धारित धनराशि से सरकार के तीन वर्ष पूरे होने का जश्न मनाना असंवेदनशीलता को दर्शाता है और इससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है।

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि भाजपा को मिल रहे जन समर्थन और देशभर में कांग्रेस की लगातार चुनावी पराजयों से कांग्रेस नेतृत्व हताश है। उन्होंने कहा कि हालिया आयोजनों में जनता की कम भागीदारी और मंच पर अव्यवस्थाओं से पार्टी कार्यकर्ताओं में भी निराशा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की दस गारंटियों का हिसाब मांग रही है, जबकि मुख्यमंत्री प्रदेश के मुद्दों के समाधान के बजाये बाहरी राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त हैं।

हिमाचल में उत्तरी रेलवे जोन को 2,216 करोड़ का बजट अमृत भारत योजना में स्टेशनों का आधुनिकीकरण

शिमला/शैल। रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने लोकसभा में कांगड़ा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज को

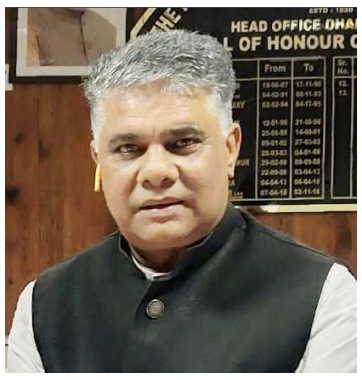

जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश को उत्तरी रेलवे जोन में शामिल किया गया है। वर्ष 2025-26 के लिए इस जोन के लिए कुल 2,216 करोड़ का बजट आबंटित किया गया है, जिसमें से अब तक 919 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

मंत्री ने बताया कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत देशभर में 1,337 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल के पालमपुर, शिमला, बैजनाथ पपरोला और अंब अंबोटा स्टेशन शामिल हैं। इनमें से पालमपुर, बैजनाथ पपरोला और अंब अंबोटा को विकसित कर दिया गया है, जबकि शिमला को मास्टर प्लानिंग के तहत कवर किया जा रहा है।

वैष्णव ने पंचरुखी रेलवे स्टेशन का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां प्लेटफार्म, शेल्टर, वेटिंग हॉल, पेयजल, शौचालय और यात्रियों के बैठने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जो तय मानकों से भी बेहतर हैं।

रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकारों, सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों से सुझाव नियमित रूप से प्राप्त होते हैं, जिन्हें पर्याप्त जांच-पड़ताल के बाद लागू किया जाता है।

अमृत भारत योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाओं जैसे वेटिंग हॉल, टॉयलेट, वाटर बूथ, बैठने की व्यवस्था, लिफ्ट, एस्केलेटर और रैंप विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

हिमाचल में रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार:रेल मंत्री

शिमला/शैल। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने सदन को बताया कि भूमि हस्तांतरण में देरी और राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की वित्तीय भागीदारी न देने के कारण कई परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

रेल मंत्री ने बताया कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन के लिए हिमाचल में 124 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, लेकिन अब तक केवल 82 हेक्टेयर भूमि ही रेलवे को हस्तांतरित की गई है। बिलासपुर से बेरी के बीच भूमि स्थानांतरित न होने से परियोजना का कार्य प्रभावित हो रहा है। 63 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की 25 प्रतिशत लागत राज्य सरकार को वहन करनी है, जबकि 75 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 6,753 करोड़ रुपये है, जिसमें 1,617 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण की लागत शामिल है। अब तक 5,252 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जबकि राज्य सरकार पर 2,711 करोड़ रुपये की देनदारी बनती है। राज्य सरकार ने अब तक केवल 847 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और 1,863 करोड़ रुपये की राशि अभी शेष है।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसकी सफलता राज्य सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009-14 के दौरान हिमाचल में रेलवे विकास के लिए 108 करोड़ रुपये दिए गए थे, जबकि वर्ष 2025-26 के लिए 2,716 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

रेल मंत्री ने बताया कि 52 किलोमीटर लंबी दौलतपुर चौक-करतोली-तलवाड़ा रेल लाइन और 1,540 करोड़ रुपये की लागत से 28 किलोमीटर लंबी चंडीगढ़-बद्दी नई रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा, बिलासपुर-लेह रेल लाइन को रक्षा मंत्रालय ने सामरिक महत्व की परियोजना घोषित किया है। इस परियोजना का सर्वे पूरा हो चुका है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। 1.31 लाख करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना के तहत 489 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण होगा, जिसमें 270 किलोमीटर हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा।

कांग्रेस 'नड्डा फोबिया' से ग्रस्त इसलिये तथ्यों से भाग रही है:सत्ती

शिमला/शैल। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक

सतपाल सत्ती ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ''जगत प्रकाश नड्डा फोबिया'' से ग्रस्त है और इसी कारण तथ्यों से भाग रही है। उन्होंने कहा कि नड्डा के शिमला दौरे और उनके बयानों से कांग्रेस असहज हो गई है, इसलिए वह भ्रम और दुष्प्रचार फैला रही है।

सतपाल सत्ती ने कांग्रेस के इस आरोप को गलत बताया कि केंद्र सरकार ने आपदा के नाम पर हिमाचल को कोई सहायता नहीं दी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने विभिन्न मदों में प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये की मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि नियमानुसार प्रक्रिया में है और इसके लिए आवश्यक प्रस्ताव व दस्तावेज राज्य सरकार को भेजने होते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, बढ़ता कर्ज और कर्मचारियों पेंशनरों की लंबित देनदारियां कांग्रेस सरकार की नीतिगत विफलताओं का परिणाम हैं। सतपाल सत्ती ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा ने हमेशा हिमाचल के हितों की मजबूती से पैरवी की है, जबकि कांग्रेस अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र और भाजपा पर निराधार आरोप लगा रही है।

पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में हिमाचल की 1945 बस्तियों का सर्वे पूरा

शिमला/शैल। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में सांसद इंदु बाला गोस्वामी को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के अंतर्गत (ग्रामीण सड़क सर्वे) ऐप के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सड़क सुविधा से वंचित 1945 योग्य बस्तियों का सर्वे किया गया है। इस सर्वे की मंत्रालय की तकनीकी शाखा द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है।

उन्होंने बताया कि योजना के पहले चरण के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की 429 बस्तियों को 295 सड़क परियोजनाओं के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसके तहत 1538 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कर इन बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।

राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण का सर्वे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा कर लिया गया है। मंत्रालय की तकनीकी टीम, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी (एनआरआईडीए), द्वारा सर्वे रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस सर्वे के तहत देशभर में सड़क सुविधा से वंचित कुल 51,343 बस्तियों का सर्वे किया गया, जिनमें से 40,547 बस्तियों को अस्थायी रूप से योग्य माना गया है। अब तक 30,129 बस्तियों का सत्यापन किया जा चुका है, जबकि शेष बस्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।

पासवान ने बताया कि केंद्र सरकार ने 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत देश की 25,000 सड़क-वंचित वस्तियों को सालभर सड़क संपर्क की सुविधा प्रदान की जाएगी।

इस चरण में मैदानी क्षेत्रों की 500 से अधिक जनसंख्या वाली, पहाड़ी क्षेत्रों की 250 से अधिक जनसंख्या वाली तथा माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों की 100 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत मार्च 2028 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2495 सड़क परियोजनाओं के माध्यम से 7,324 किलोमीटर लंबी सड़कों और 211 पुलों का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जनमन योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर एक करोड़ रुपये की लागत से लगभग 8000 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर 8000 किलोमीटर लंबी सड़कों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

हिमाचल में 1,818,925 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत, मिनी केंद्रों को पूर्ण केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा

शिमला/शैल। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री

ठाकुर ने राज्यसभा में सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को बताया कि हिमाचल प्रदेश में कुल 1,818,925 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। वर्तमान में राज्य में कोई मिनी आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है।

सावित्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने देशभर के सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्रों में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक पूर्ण केंद्र में एक वर्कर और एक हेल्पर तैनात किए जाएंगे, ताकि पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत सेवाएं प्रभावी रूप से प्रदान की जा सकें।

आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के मापदंड भी तय किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 400 जनसंख्या पर एक केंद्र, 800 पर दो केंद्र, 1,600 पर तीन केंद्र। शहरी क्षेत्र में 800 जनसंख्या पर एक केंद्र, 1,600 पर दो केंद्र, 2,400 पर तीन केंद्र। मिनी केंद्र ग्रामीण 150 जनसंख्या और शहरी 400 जनसंख्या पर।

मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों के वर्कर्स को 4,500 रुपये और मिनी केंद्रों के वर्कर्स को 3,500 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

अभिनंदन रैली में भाजपा नेताओं का कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में आयोजित अभिनंदन रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस सरकार पर एकजुट होकर तीखा राजनीतिक हमला बोला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मंच से राज्य सरकार की नीतियों, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। नेताओं ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी, कुशासन, आर्थिक कुप्रबंधन और जनता को गुमराह करने जैसे गंभीर आरोप लगाये। रैली में भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद विकास की गति थम गई है और जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को तीन वर्षों में विकास के पथ से पीछे धकेल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस हिमाचल को भाजपा सरकार ने आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में मजबूत किया था, उसे वर्तमान सरकार ने कर्ज और अव्यवस्था में झोंक दिया है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय जनता से बड़े-बड़े वादे किये, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को निभाने में पूरी तरह विफल रही।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। विकास कार्य ठप पड़े हैं, योजनाएं कागजों तक सीमित हैं और आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल सेवाओं से परेशान है। नड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित से ज्यादा सत्ता बचाने और राजनीतिक बयानबाजी में व्यस्त है।

जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने और उनका श्रेय खुद लेने की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को दी जा रही सहायता को जानबूझकर कम करके दिखाया जा रहा है।

हिमाचल में केंद्र से मिली सहायता का विवरण देते हुये जेपी

नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा राहत के लिए 3789 करोड़ रुपये, स्मार्ट सिटी के लिए 1000 करोड़ से अधिक, वाइब्रेंट विलेज योजना, मेडिकल कॉलेज, एम्स बिलासपुर, बल्क ड्रग पार्क, फोरलेन परियोजनाएं और बद्दी को फार्मा हब के रूप में विकसित करने के लिए राशि दी। नड्डा ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को 2000 करोड़ से अधिक की विशेष सहायता और 1442 करोड़ रुपये का जायका फंड स्वीकृत किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कई योजनाओं में केवल 50 प्रतिशत राशि ही खर्च की। नड्डा ने कहा कि सड़क, रेल, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बड़े प्रोजेक्ट प्रदेश में आये हैं, वे केंद्र सरकार की देन हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र के साथ टकराव का रास्ता अपनाया है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार जो धन का सही उपयोग न कर सके, सत्ता में बने रहने की हकदार नहीं है।

जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक भी ठोस परियोजना केंद्र के पास नहीं भेजी। नड्डा ने चुनौती दी कि अगर कांग्रेस सरकार कोई प्रोजेक्ट लाए, तो केंद्र सरकार उसे तुरंत स्वीकृत करेगी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और माफिया बेलगाम हो चुके हैं। बिंदल ने कहा कि नशा माफिया, खनन माफिया और भूमि माफिया को सरकार का संरक्षण मिल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी सबसे अधिक प्रभावित हो रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने में नाकाम रही है और युवाओं में निराशा बढ़ रही है। सरकारी भर्तियां धीमी पड़ी हैं और जिन नौकरियों की घोषणा की गई थी, वे अब तक पूरी नहीं हुई। बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार केवल घोषणाएं करती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता।

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने हिमाचल को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान कर्ज लेने और खर्च बढ़ाने पर है, जबकि आय बढ़ाने की कोई ठोस योजना नहीं है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के समय शुरू की गई कई योजनाओं को या तो बंद कर दिया गया या उन्हें धीमा कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते जनहित की योजनाओं को नुकसान पहुंचाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया था, लेकिन वर्तमान सरकार उन्हें संभालने में भी नाकाम रही है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसदअनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं और कर्मचारियों दोनों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय रोजगार और भत्तों को लेकर किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन आज युवा दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की जा रही है और सरकार केवल तात्कालिक फैसले लेकर भविष्य की समस्याएं खड़ी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन स्थायी समाधान नहीं दिया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार महिलाओं और गरीबों के नाम पर राजनीति कर रही है। योजनाओं की घोषणाएं तो की गई, लेकिन उनका लाभ सीमित लोगों तक ही पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं है और कई जगहों पर भेदभाव किया जा रहा है।

पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए बार-बार पूर्व सरकारों पर दोष मढ़ रही है। कश्यप ने कहा कि सत्ता में आये तीन वर्ष हो चुके हैं, लेकिन सरकार अब भी बहानेबाजी से बाहर नहीं निकल पायी है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार के समय शुरू हुए कई अधूरे प्रोजेक्ट आज भी पूरे नहीं हो पाए हैं, जिससे जनता को नुकसान हो रहा है।

भाजपा नेताओं ने आपदा प्रबंधन को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय सरकार की तैयारियां अपर्याप्त रहीं और राहत कार्यों में देरी हुई। नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायता का सही उपयोग नहीं किया गया और प्रभावित लोगों को समय पर राहत नहीं मिली।

रैली के दौरान भाजपा नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं और पारदर्शिता की कमी साफ दिखाई दे रही है। नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार के समय भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण था, लेकिन वर्तमान सरकार में जवाबदेही कमजोर हुई है।

अभिनंदन रैली के माध्यम से भाजपा नेताओं ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि पार्टी प्रदेश में कांग्रेस सरकार की नीतियों और फैसलों को जनता के बीच उजागर करेगी। नेताओं ने कहा कि भाजपा जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेगी और सरकार की विफलताओं को सामने लाएगी।

रैली में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पार्टी नेतृत्व के प्रति विश्वास जताया। नेताओं ने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत विकल्प के रूप में जनता के बीच मौजूद है और आने वाले समय में जनसमर्थन के बल पर फिर से सत्ता में लौटेगी।

मंडी में कांग्रेस का जन संकल्प

.....पृष्ठ 1 का शेष

ने उल्लेखनीय प्रगति की है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुशासन, आबकारी नीति में सुधार और नए राजस्व स्रोतों के सृजन से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है।

सम्मेलन के दौरान सरकार की तीन वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक और वृत्तचित्र का विमोचन किया गया। विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी, पार्टी पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे।

जन संकल्प सम्मेलन के माध्यम से मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने यह संदेश दिया कि बीते तीन वर्षों में रखी गई विकास की नींव पर आने वाले समय में और तेज गति से कार्य किया जाएगा, ताकि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर, समावेशी और प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके।